रूपांतरण प्रायोगिक संयंत्र को कोई प्राथमिकता देने की गुंजाइश नहीं है ।

Utilisation of Lignite found in South Arcot district and Pondichery

414. SHRI S. VIDUTHALAI VIRUM-BL Will the Minister of ENERGY be phased to state the steps taken to utilise tltc lignite deposits found in Jayamkondam (S'uuth Arcot district) and adjacent areas in Tamilnadu and some places in Poadieherry?

[r: HE MINISTER OF ENERGY (SHRI KALYAN SINGH KALVI): Neyveli Lignite Corporation is at present carrying out detailed Geological exploration for lignite in the Jayamkondam area in Tirchy district and adjacent areas in South Arcot Oiiitrict in Tamilnadu and Bahur Area in Poadieherry. Hydrological investigations for safe mining of lignite is yet to be 'ra-iated by NLC. Feasibility report|project report will be prepared only after tcvnpletion of these investigations for training of lignite and settino up a power sttaion.

राजस्थान में विद्युत उत्पादन के लिये नई योजनाएं

415. **डा. अवरार अहमद :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में विद्युत उत्पादन के लिये कौन-कौन सी योजनायें केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं तथा ये कब तक पूरी हो जायेंगी ;

(ख) वर्तमान में बनाई जा रही नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) राजस्थान में इस समय विद्युत की कुल खपत कितनी है और उत्पादन कितना किया जा रहा है ; और

(घ) क्या यह सही है कि विद्युत की कमी से राजस्थान के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबन राव ढाकणे) : (क) और (ख) राज्य क्षेत्र की स्कीमों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है । **(नीचे देखिए)**

(ग) अप्रैल, 90 से नवम्बर, 90 की अवधि के दौरान 7170 मि.यू. की मांग की तुलना में विद्युत की उपलब्धता 7065 मि.यू. थी जिसके परिणामस्वरूप 105 मि०यू० (1.5%) की सीमांत कमी रही ।

(घ) विकास संबंधी प्रक्रिया अनेक पहलुओं पर निर्भर करती है और विद्युत की कमी इनमें से एक है ।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगा.)	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
राज्य विद्युत				
1.	सूरतगढ़ चरण–I	2×250=500	1253.3	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा यह स्कीम तकनीकी आर्थिक दृष्टि से ठीक पाई गई है, बशर्ते

1	2	3	4	5
				पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नागर विमानन विभाग की स्वीकृति एवं के.वि.प्रा. से संबद्ध पारेषण प्रणाली हेतु स्वीकृति प्राप्त हो जा ।
2.	धौलपुर	2×210=420	759.3	राज्य सरकार द्वारा एक नये परियोजना स्थल का अभिनिर्धारण किया गया जो पर्यावरण के मानदंडों को पूरा कर सकता है । यदि यह स्थल पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त पाया जाता है तो यूनिट की आकृति संशोधित करके 250 मेगावाट करने की आवश्यकता पड़ेगी ।
3.	चित्तौड़गढ़	2×210=420	451.8	जल एवं अन्य निवेश सुनिश्चित किये जाने हेतु राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा और जांच की जानी है । राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को चित्तौड़गढ़ एवं मंडलगढ़ के बीच एक बड़ा ताप विद्युत केन्द्र अवस्थित करने की साध्यता की जांच करने हेतु भी जुलाई, 1989 में सलाह दी गई थी ताकि बेरख नदी से उपलब्ध जल का समुपयोग हो सके । राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा इन परियोजनाओं के लिये पर्यावरणीय दृष्टि से भी स्वीकृति प्राप्त की जानी है ।
	मंडलगढ़	3×210=630	554.7	
जल विद्युत				
1.	राहूघाट	4×40=160	415.0	रिपोर्ट फरवरी, 1988 में, मध्य प्रदेश राज्य के साथ अन्तर्राज्यीय पहलुओं के समाधान के बाद फिर से प्रस्तुत किये जाने हेतु लौटा दी गई थी । परियोजना प्राधिकारियों को संशोधित रिपोर्ट शीघ्र तैयार करने हेतु जुलाई, 1990 में अनुस्मरण कराया गया था ।

1	2	3	4	5
2.	जःखाम संशोधि	1×5.5=5.5	8.00	रिपोर्ट नवम्बर, 1988 में परियोजना प्राधिकारियों को लौटा दी गई थी । परियोजना प्राधिकारियों से, संशोधित रिपोर्ट यूनिट के आकार, यूनिटों की संख्या अपेक्षित व्यस्ततमकालीन घंटों एवं लागत अनुमानों आदि की समीक्षा करने के बाद पुनः प्रस्तुत करने के लिये दिसम्बर; 1989 में अनुरोध किया गया था ।
3.	जावई	2×0.6+ 2×0.6=2.4	6.00	राज्य प्राधिकारियों से सिंचाई विभाग द्वारा विद्युत लाभों के मूल्यांकन हेतु स्वीकृत रूप में वास्तविक प्रक्षेपण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था । रिपोर्ट नवम्बर, 1988 में लौटा दी गई थी ।
4.	माउंट आबू बहुउद्देशीय परियोजना	2×5=10	16.00	इस स्कीम के एक बहुउद्देशीय परियोजना होने के कारण इसके विद्युत भाग हेतु के.वि.प्रा. द्वारा तभी विचार किया जा सकता है जब तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा परियोजना तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दी जाय । परियोजना प्राधिकारियों को जलकपाट की लम्बाई एवं अन्य सिविल संरचनाओं की लंबाई कम करने हेतु पावर हाऊस के कार्यस्थल के विकल्प पर विचार करने हेतु सलाह दी गई थी । परियोजना प्राधिकारियों को संशोधित रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराने के लिये अप्रैल, 1990 में अनुस्मारित किया गया था ।
5.	कोटा पम्पड स्टोरेज	2×100=200	158.00	रिपोर्ट अक्तूबर, 1989 में लौटा दी गई थी और उसके विकल्पों के लिये और जांच एवं परीक्षण करने के बाद उसे पुनः प्रस्तुत किये जाने हेतु कहा गया था । राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा यह स्कीम छोड़ दी गई थी ।